CENTRE OF EXCELLENCE FOR DAIRY SKILLS IN INDIA

+91 7428706078
info@cedsi.in

CEDSI TIMES

Your Skilling Partner...

FSSAI ने डेयरी कंपनियों को भ्रामक A1 और A2 लेबल हटाने का आदेश दिया

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने डेयरी कंपनियों को दूध, घी, मक्खन और दही जैसे उत्पादों पर A1 और A2 लेबल का उपयोग बंद करने का निर्देश दिया है। ये लेबल दो प्रकार के दूध प्रोटीन के बीच अंतर करते हैं, जिसमें A1 होलस्टीन जैसी नस्लों में और A2 जर्सी गायों जैसी नस्लों में पाया जाता है। जबकि कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि A2 दूध पचाने में आसान हो सकता है, वैश्विक शोध अनिर्णायक है, इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं है कि यह स्वास्थ्यवर्धक या बेहतर है।

FSSAI इन दावों को भ्रामक और खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के साथ असंगत मानता है, जिससे यह चिंता बढ़ रही है कि उपभोक्ताओं को गलत तरीके से यह विश्वास दिलाया जा सकता है कि एक प्रकार का दूध दूसरे से बेहतर है।

कंपनियों को अपनी पैकेजिंग से इन लेबल को हटाने के लिए छह महीने का समय दिया गया है, जबकि ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म को संबंधित दावों को तुरंत हटाना होगा। FSSAI के इस कदम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को गलत सूचनाओं से बचाना और डेयरी उद्योग में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

मिल्मा ने उत्तर केरल के डेयरी किसानों के लिए 8.52 करोड़ रुपये के ओणम उपहार की घोषणा की

मालाबार क्षेत्रीय सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ (मिल्मा) ने उत्तरी केरल के डेयरी किसानों के लिए ₹8.52 करोड़ के ओणम उपहार की घोषणा की है। इन लाभों में दूध के लिए अतिरिक्त पारिश्रमिक और मवेशियों के चारे के लिए सब्सिडी शामिल है, जिसका उद्देश्य जुलाई और अगस्त के दौरान भारी बारिश और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करना है। यह निर्णय 24 अगस्त को मिल्मा के प्रशासनिक पैनल की बैठक के दौरान लिया गया।

इस पहल से पूरे क्षेत्र के करीब एक लाख डेयरी किसान और 1,200 सहकारी समितियां लाभान्वित होंगी। ओणम उपहार का उद्देश्य उन किसानों की सहायता करना है, जिन्हें प्रतिकूल मौसम की वजह से बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।

मिल्मा का यह कदम डेयरी किसानों की आजीविका की सुरक्षा के लिए उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उन्हें मुश्किल समय में आवश्यक सहायता मिले। इस पैकेज से त्योहारी सीजन के दौरान बहुत जरूरी वित्तीय राहत मिलने और मनोबल बढ़ाने की उम्मीद है, जो डेयरी समुदाय के भीतर लचीलापन बढ़ाने में सहकारी की भूमिका को रेखांकित करता है।

केरल सरकार डेयरी किसानों के लिए साल भर किफ़ायती हरा चारा सुनिश्चित करेगी

इस परियोजना से लगातार और किफ़ायती हरे चारे की महत्वपूर्ण ज़रूरत को पूरा करने की उम्मीद है, जो राज्य में डेयरी खेती को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। इस पहल का उद्देश्य चारे के उत्पादन को बढ़ावा देना और डेयरी किसानों को लगातार आपूर्ति सुनिश्चित करना है, ख़ास तौर पर चारे की कमी के समय।

केरल सरकार डेयरी किसानों को साल भर किफ़ायती दामों पर हरा चारा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक व्यापक परियोजना शुरू करने जा रही है। पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री जे. चिंचुरानी ने मिलमा के तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ (TRCMPU) द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के जिला-स्तरीय उद्घाटन के दौरान इस पहल की घोषणा की।

मंत्री चिंचुरानी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह परियोजना डेयरी क्षेत्र की उत्पादकता और लाभप्रदता बढ़ाने के सरकार के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप है। हरे चारे को ज़्यादा सुलभ बनाकर, सरकार का लक्ष्य डेयरी किसानों पर वित्तीय बोझ को कम करना है, साथ ही स्वस्थ पशुधन और बेहतर दूध उत्पादन को बढ़ावा देना है।

मध्य प्रदेश सरकार आवारा पशुओं को आश्रय स्थलों तक पहुंचाने के लिए 2,000 से अधिक स्वयंसेवकों को नियुक्त करेगी

मध्य प्रदेश सरकार ने आवारा पशुओं को आश्रय स्थलों तक पहुंचाने के लिए 2,000 से अधिक स्वयंसेवकों को नियुक्त करने का निर्णय लिया है। इन स्वयंसेवकों को ₹5,000 से ₹10,000 तक का मानदेय मिलेगा, जिन्हें जिला पंचायतों और शहरी विकास विभागों द्वारा नियुक्त किया जाएगा। मानदेय प्रत्येक क्षेत्र में आवारा पशुओं की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

आवारा पशुओं को नियंत्रित करने के लिए 21 अगस्त को शुरू किए गए 15 दिवसीय अभियान के तहत अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) के नेतृत्व में पांच सदस्यीय समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया। बरसात के मौसम में आवारा पशु अक्सर सड़कों पर जमा हो जाते हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी होती है। इस समस्या से निपटने के लिए, राजमार्गों के पास स्थित ग्राम पंचायतें मवेशियों को आश्रय स्थलों तक पहुंचाने और जहां आवश्यक हो, वहां अस्थायी आश्रय स्थलों के निर्माण के लिए जिम्मेदार स्वयंसेवकों को नियुक्त करेंगी।

जिला प्रशासन को मवेशियों को सुरक्षित तरीके से स्थानांतरित करने के लिए 6 लाख रुपये की लागत वाली हाइड्रोलिक कैटल-लिफ्टिंग ट्रॉलियां खरीदने का भी निर्देश दिया गया है। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मलय श्रीवास्तव ने इस बात पर जोर दिया कि जिलों को स्थानीय जरूरतों के हिसाब से स्वयंसेवकों को नियुक्त करने और उनका मानदेय निर्धारित करने की स्वायत्तता है। इसके अलावा, पशुपालन विभाग ने पहल का समर्थन करने के लिए पशु रोगी कल्याण समिति कोष से प्रति जिले 5 लाख रुपये आवंटित किए, जिसमें जीपीएस से लैस वाहनों का उपयोग करके राजमार्गों पर गायों की गश्त करना भी शामिल है।

त्यौहारी सीजन में मांग बढ़ने पर दूध संग्रहण बढ़ाएगा इंदौर सहकारी दुग्ध संघ

आगामी त्यौहारी सीजन में मांग में तेज वृद्धि की आशंका के मद्देनजर इंदौर सहकारी दुग्ध संघ अपना दूध संग्रह बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। सहकारी की खरीद क्षमता के करीब पहुंचते हुए, दैनिक दूध की खपत पहले ही करीब 2.35 लाख लीटर तक बढ़ गई है। त्यौहारी सीजन में मिठाई उत्पादन और घरेलू उपयोग के लिए दूध की मांग बढ़कर 14 लाख लीटर प्रतिदिन तक पहुंचने की उम्मीद है, इसलिए सहकारी ने बढ़ती जरूरत को पूरा करने के लिए और अधिक डेयरी किसानों को जोड़ने की योजना बनाई है।

इससे पहले, दुग्ध संघ के पास जुलाई तक लगभग 30,000 लीटर का दैनिक अधिशेष था, लेकिन बढ़ती खपत के स्तर ने उस अंतर को कम कर दिया है। वर्तमान में, दैनिक दूध संग्रह लगभग 12-12.5 लाख लीटर है, जो अनुमानित दैनिक खपत के करीब है। स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, सहकारी अपनी दूध खरीद को बढ़ाने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है।

घी और पनीर जैसे डेयरी उपोत्पादों की बिक्री में हाल की वृद्धि भी आशाजनक रही है, अगस्त के अंत तक 26,000-27,000 किलोग्राम तक पहुंचने की उम्मीद है। इंदौर दुग्ध विक्रेता संघ का मानना है कि मिठाई निर्माताओं और परिवारों की ओर से बढ़ती मांग से इस उछाल को बढ़ावा मिलेगा, जिससे सहकारी संस्था को आगामी व्यस्त और सफल त्यौहारी सीजन के लिए तैयार रहने के लिए प्रेरित किया जा सकेगा।

पूर्वोत्तर राज्यों ने दिल्ली बैठक में डेयरी विकास और पशुधन योजनाओं की समीक्षा की

नई दिल्ली में आयोजित एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय समीक्षा बैठक में, पशुपालन और डेयरी सचिव, श्रीमती अलका उपाध्याय ने पूर्वोत्तर में प्रमुख पशुधन और डेयरी विकास कार्यक्रमों की प्रगति पर चर्चा की। असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के उच्च-स्तरीय अधिकारियों ने भाग लिया, जिसमें राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम), राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी) और राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) जैसी महत्वपूर्ण पहलों के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया गया।

श्रीमती उपाध्याय ने क्षेत्र में उत्पादक गोजातीय पशुओं की संख्या को बढ़ाने के लिए अनुरूप रणनीतियों की आवश्यकता पर बल दिया और अधिकारियों से चारे की कमी को दूर करने और एनपीडीडी के तहत विकसित बुनियादी ढांचे का अधिकतम उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने संगठित डेयरी क्षेत्र के विस्तार, स्वदेशी दूध उत्पादों को बढ़ावा देने और मजबूत विपणन योजनाओं को विकसित करने के महत्व पर प्रकाश डाला।

बैठक में एनएलएम के तहत उद्यमिता पहलों की सफलता की भी समीक्षा की गई और श्रीमती। उपाध्याय ने राज्यों को पशुधन क्षेत्र में स्थानीय उद्यमिता को बढ़ाने के लिए उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। सचिव ने आगामी 21वीं पशुधन जनगणना के लिए सटीक डेटा संग्रह के महत्व पर जोर दिया, जो पशुपालन क्षेत्र में भविष्य की नीति निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होगा।

पुदुकोट्टई जिले ने दूरदराज के गांवों के लिए आठ मोबाइल पशु चिकित्सा क्लीनिक शुरू किए

ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा देखभाल को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, पुदुकोट्टई जिले में आठ मोबाइल पशु चिकित्सा क्लीनिक शुरू किए गए हैं। इन क्लीनिकों का उद्देश्य दूरदराज के गांवों में पशुओं को मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना है, जहां पशु चिकित्सा अस्पतालों और औषधालयों तक पहुंच नहीं है।

प्रत्येक मोबाइल क्लीनिक विभिन्न पशुधन रोगों के इलाज के लिए आवश्यक उपकरणों, दवाओं और उपकरणों से पूरी तरह सुसज्जित है। प्रत्येक वाहन को एक समर्पित पशु चिकित्सक और एक सहायक नियुक्त किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ज़रूरतमंद पशुओं को पेशेवर देखभाल उपलब्ध हो। मोबाइल क्लीनिक जिले के सबसे अलग-थलग इलाकों में जाएंगे, जहां महत्वपूर्ण पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाएंगी जो अन्यथा उपलब्ध नहीं होंगी।

इस पहल से इन वंचित क्षेत्रों में पशुधन स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, जिससे बीमारी के प्रकोप को रोकने और समग्र पशु कल्याण में सुधार करने में मदद मिलेगी। किसानों को सीधे पशु चिकित्सा देखभाल प्रदान करके, कार्यक्रम पशुधन की भलाई का समर्थन करता है, जो पुदुकोट्टई में ग्रामीण समुदायों की आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है।

ये पहल डेयरी किसानों की आजीविका में सुधार, उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और स्थायी डेयरी प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। व्यापक सहायता पैकेज का उद्देश्य डेयरी क्षेत्र और उसमें काम करने वाले लोगों की भलाई को बढ़ावा देना है।

मोबाइल पशु चिकित्सा क्लीनिकों की यह शुरुआत पशु स्वास्थ्य में सुधार और कृषि अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए जिले की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। इन क्लीनिकों द्वारा प्रदान की जाने वाली निःशुल्क सेवाओं से किसानों को बहुत लाभ होने की उम्मीद है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि उनके पशुओं को उनके स्थान की परवाह किए बिना आवश्यक देखभाल मिले।

हम कौन हैं?

सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर डेरी स्किल्स इन इंडिया (सीईडीएसआई) "सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर एग्रीकल्चर स्किल्स इन इंडिया (सीईएएसआई)" के तहत काम कर रहा है, यह एक स्वायत्त संगठन है जो "**एग्रीकल्चर स्किल कौंसिल ऑफ़ इंडिया (ASCI)**" के तत्वावधान में काम कर रहा है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के संगठित और असंगठित क्षेत्रों में लगे किसानों, वेतनभोगी श्रमिकों, स्व-रोज़गार पेशेवरों, विस्तार श्रमिकों आदि के कौशल और क्षमता निर्माण के लिए **कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई**) के तहत काम करना।

सीईएएसआई कृषि के विभिन्न उप-क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्रों का एक शीर्ष संगठन है।

- सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर डेरी स्किल्स इन इंडिया (सीईडीएसआई)
- सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर हॉर्टिकल्चर स्किल्स इन इंडिया (सीईएचएसआई)
- सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर फार्म मेकेनिज़शन स्किल्स इन इंडिया (सीईएफएमआई)

सीईडीएसआई सदस्यता उद्योग के नेताओं, नीति निर्माताओं, विकास चिकित्सकों, डेयरी वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, छात्रों और किसानों को डेयरी उद्योग के लिए आसन्न महत्व के मुद्दों पर बहस और चर्चा करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करेगी।

+91 7428706078

info@cedsi.in

www.cedsi.in Follow us on Facebook Cedsi Dairyskills Follow us on Twitter @CEDSI_India Follow us on Instagram @cedsi_india Follow us on linkedin Cedsi dairy COE

Centre of Excellence for Dairy Skills in India

Join Our Membership Drive and Get Benefits of

- Platform to interact with other members in the sector
- Networking opportunities with corporate leaders and government authorities
- Special costs of training in Skill India Certified Programmes
- Access to our Journal and Publications
- Expert advice in day-to-day operations and management of livestock /farm productions
- Free registration on the job portal and regular updates on job vacancies in the sector
- Recognize your organization with CEDSI Yearly Awards and Recognition
- Chance to reach across the board through advertising in our press releases, news and articles
- Consultative and advisory services to help members
- Consulting and advisory services to help members
- Periodic e-newsletter for the latest news, govt. announcement and schemes in dairy sectors
- Updates on training programs of CEDSI and access to the training calendar

Who Can Become a Member -

Corporates/ Cooperatives | NGO's/CSR Foundations | Dairy Farmers | Students | Professional

www.cedsi.in 17th July 2024 @cedsi_india

CEDSI : रविविंग स्किल्स एंड जनरेटिंग लाइवलीहुड

किसानों/छात्रों/उद्यमियों के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम

- डेयरी किसान / उद्यमी
- डेयरी फार्म पर्यवेक्षक
- डेयरी कार्यकर्ता
- पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता
- कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन
- पशु चिकित्सा क्षेत्र सहायक
- पशु चिकित्सा नैदानिक सहायक
- बछड़ा पालन
- कृषि उपकरण तकनीशियन
- डेयरी फार्म अर्थशास्त्र और प्रबंधन
- उद्योग संरेखित प्रमाणन कार्यक्रम (बेरोजगार युवा और छात्र)

एफपीओ उन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम

- उत्पाद प्रौद्योगिकी और प्रक्रियाओं पर एफपीओ सदस्य अभिविन्यास।
- एफपीओ मार्केट लिंकेज
- एफपीओ शासन
- एफपीओ लेखा

डेयरी कॉरपोरेट्स और सहकारी समितियों के लिए प्रमुख कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम

- चिलिंग प्लांट तकनीशियन
- बल्क मिल्क कूलर ऑपरेटर
- ग्राम स्तरीय दुग्ध संग्रह केन्द्र पर्यवेक्षक
- दूध परीक्षक
- ग्रीन हाउस गैसों का शमन
- दूध की गुणवत्ता आश्वासन
- मिल्क डिलीवरी बॉय
- दूध खरीद और इनपुट पर्यवेक्षक
- डेयरी उद्योग में अपशिष्ट प्रबंधन
- चारा और चारा प्रबंधन
- स्वच्छ दूध उत्पादन
- निर्णय समर्थन प्रणाली / डेटा विश्लेषिकी

सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर डेरी स्किल्स इन इंडिया